



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

15/5/98
28/5/98

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 16, 1998 (वैशाख 26, 1920)
No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 16, 1998 (VAISAKHA 26, 1920)

हम यहाँ में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 369	भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (सब शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वयं को उपविधियों भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित हों)	पृष्ठ *
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	411	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	1	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, निपटकर और महालेखा-परीक्षक, सैन्य लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबंध और पदोन्नतियों कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	461
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	729	भाग III—खण्ड 2—सैन्य कार्यालय द्वारा जारी की गई वेस्टा और विज्ञापन में प्रकाशित अधिसूचनाएं और नोटिस	659
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड 3—सूक्ष्म आयुक्तों के आदेशों के अधीन प्रथम द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड 4—विभिन्न अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं।	1583
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के विल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—नगर-सरकारी व्यक्तियों और नगर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	101
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (सब शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वयं के आदेश और उप-विधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—ग्रामीण और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के घोषणों की दस्तावेज वाला अनुपकरण	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (सब शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेशों और अधिसूचनाएं	*		

नोट: नोट नं. 1

CONTENTS

	PAGE		PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	369	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 of Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	418	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	461
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	729	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	659
PART I—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1583
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by private individuals and private Bodies	101
PART II—SECTION 2—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc., both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और संघीय निकायों द्वारा जारी की गई विभिन्न विधियों, विनियमों तथा आदेशों और संघीय अधिसूचनाएँ

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल 1998

संकल्प

सं. 1(1)/95-खान-6—भारत सरकार ने अपने दिनांक 15-6-1995 के समसंख्यक संकल्प (प्रति संलग्न) द्वारा ग्रनाइट उद्योग के विकास की देखरेख हेतु एक ग्रनाइट उद्योग परिषद का गठन किया था जिसका कार्यकाल दो वर्ष की अवधि अर्थात् 15-6-1995 तक था। भारत सरकार का विचार है कि ग्रनाइट विकास परिषद का कार्यकाल उन्हीं विचारार्थ विषयों सहित 31-3-2000 तक बढ़ाना ग्रनाइट उद्योग के विकास और ग्रनाइट के निर्यात के हित में होगा जो पैराग्राफ 2 में उद्धृत किए गए हैं। सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि ग्रनाइट विकास परिषद के गठन में मामूली संशोधन की जरूरत है और तबनुसार यह निर्णय लिया गया है कि इसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे :—

अध्यक्ष

1. सचिव
खान मंत्रालय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

सदस्यगण

2. संयुक्त सचिव
वाणिज्य मंत्रालय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।
(वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा)
3. संयुक्त सचिव
पर्यावरण और वन मंत्रालय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।
(पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा)
4. सचिव
उद्योग और वाणिज्य विभाग,
आन्ध्र प्रदेश सरकार,
हैदराबाद।

5. सचिव
खान और ऊर्जा विभाग,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।
6. सचिव
उद्योग विभाग,
तमिलनाडु सरकार,
चेन्नई।
7. प्रधान सचिव
हस्तात और खान विभाग,
उड़ीसा सरकार,
भुवनेश्वर
8. सचिव
वाणिज्य और उद्योग विभाग,
कर्नाटक सरकार,
बैंगलूर।
9. अपर मुख्य सचिव
उद्योग और खान विभाग,
गुजरात सरकार,
गांधीनगर।
10. आयुक्त और सचिव
उद्योग विभाग,
केरल सरकार,
तिरुवनन्तपुरम।
11. महानिदेशक
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण,
कलकत्ता।
12. महानियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो,
नागपुर।
13. अध्यक्ष
(श्री विमल पीदार)
वाल इंडिया ग्रनाइट एण्ड
स्टोन एसोसिएशन,
बैंगलूर।

14. महासचिव
(श्री आर. के. शर्मा)
फेडरेशन आफ इण्डियन,
मिनरल इण्डस्ट्रीज,
नई दिल्ली।

15. श्री आर. पी. झुंझुवाला
ग्रैफाइट लि.,
उड़ीसा।

16. श्री जे. पी. अग्रवाल
पैसिफिक ग्रैनाइट
उदयपुर।

17. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
आंध्र प्रदेश मिनरल
डेवलपमेंट कार्पोरेशन
हैदराबाद।

18. संयुक्त सचिव
(श्री एस. पी. गुप्ता)
खान मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली।

सदस्य-सचिव

19. निदेशक
(श्री एन. सान्याल)
खान मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली।

2. ग्रैनाइट विकास परिषद के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार
होंगे :—

- (1) ग्रैनाइट खानों की स्थिति का आकलन रूप से आकलन और समीक्षा करना और इस खनिज के तेजी से विकास हेतु उपायों की सिफारिश करना।
- (2) खानों में लगाई गई प्रौद्योगिकी का आकलन करना और इस खनिज की प्रौद्योगिकी के संवर्धन और वैज्ञानिक विद्योहन के उपाय सुझाना।

(3) ग्रैनाइट पर लगने वाले वर्तमान कर और रायल्टी छूट का आकलन करना और ग्रैनाइट में निवेश को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए उपाय सुझाना।

(4) ग्रैनाइट और इसके उत्पादों के मूल्य परिवर्धन के उपाय सुझाना।

(5) अन्य कोई पहलू जिसे परिषद देश में ग्रैनाइट खनन और उद्योग के हित में महत्वपूर्ण समझती है।

एन. सान्याल
निदेशक

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 1998

सं. 6/2/97-पारंपरण 1—विद्युत मंत्रालय के दिनांक 4-8-97 के संकल्प संख्या 6/2/97 का आंशिक रूप से संशोधित करते हुए सचिव, विद्युत विभाग, सिविक कम सरकार को धार्मिक मूल्य अभियन्ता, विद्युत विभाग, सिविक कम सरकार की जगह पर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।

अन्य संघटक सदस्य वही रहेंगे।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त संकल्प बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों तथा सिविक कम की राज्य सरकार, दामोदर घाटी निगम, दूगपूर परियोजना लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड, भारत सरकार के सभी मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार का प्रेषित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जे. वासुदेवन
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 24th April 1998

RESOLUTION

No. 1/1/95-M. VI.—A Granite Development Council for overseeing the development of the Granite Industry was constituted by the Government of India vide its Resolution of even number dated 15-6-95 (copy enclosed), the tenure of which was for a period of two years, i.e. upto 15-6-97. The Government of India has come to the view that it will be in the interest of development of granite industry and export of granite to extend the tenure of Granite Development Council upto

31-3-2000 with the same Terms of Reference which have been reproduced in paragraph 2. It has further been decided by Government that the composition of the Granite Development Council needs minor modifications and accordingly, it has been decided that it should comprise of the following :

CHAIRMAN

1. Secretary
Ministry of Mines
Govt. of India
New Delhi

MEMBERS

2. Joint Secretary
Ministry of Commerce
Government of India
New Delhi
(To be nominated by M/o Commerce)
3. Joint Secretary
Ministry of Environment & Forests
Government of India
New Delhi
(To be nominated by M/o Env. & Forests)
4. Secretary
Industries & Commerce Department
Government of Andhra Pradesh
Hyderabad
5. Secretary
Mines & Energy Department
Government of Rajasthan
Jaipur
6. Secretary
Industries Department
Government of Tamil Nadu
Chennai
7. Principal Secretary
Steel & Mines Department
Government of Orissa
Bhubaneswar
8. Secretary
Commerce & Industries Department
Government of Karnataka
Bangalore
9. Additional Chief Secretary
Industries & Mines Department
Government of Gujarat
Gandhinagar
10. Commissioner & Secretary
Industries Department
Government of Kerala
Thiruvananthapuram
11. Director General
Geological Survey of India
Calcutta
12. Controller General
Indian Bureau of Mines
Nagpur
13. President
(Shri Vinay Poddar)
All India Granite & Stone Association
Bangalore
14. Secretary-General
(Shri R. K. Sharma)
Federation of Indian Mineral Industries
New Delhi
15. Shri R. P. Jhunjhunwala
Grapco Granites Ltd.
Orissa
16. Shri J. P. Aggarwal
Pacific Granites,
Udaipur
17. Chairman-cum-Managing Director
Andhra Pradesh Mineral Dev. Corpn.
Hyderabad

18. Joint Secretary
(Shri S. P. Gupta)
Ministry of Mines
Government of India
New Delhi

MEMBER-SECRETARY

19. Director
(Shri N. Sanyal)
Ministry of Mines
Government of India
New Delhi
3. The Terms of Reference of the Granite Development Council will be as follows :
 - (1) To assess and review periodically the status of granite mines and recommend measures for speedy development of the mineral.
 - (2) To assess technology employed in the mines and recommend measures for upgradation of technology and scientific exploitation of the mineral.
 - (3) To assess present taxation and royalty structure on granite and suggest measures to make investment in granite more attractive.
 - (4) To recommend measures for increasing value addition in granite and its products.
 - (5) Any other aspect which the Council deems important in the interest of development of granite mining and industry in the country.

N. SANYAL
Director

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 27th April 1998

No. 6/2/97-Trans.—In partial modification of this Ministry of Power Resolution No. 6/2/97-Trans. dated 4-8-97, the Secretary, Deptt. of Power, Govt. of Sikkim may be nominated as member of Eastern Regional Electricity Board in place of the Addl. Chief Engineer, Deptt. of Power, Govt. of Sikkim.

The other constituent members remain the same.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the Governments and State Electricity Boards of Bihar, Orissa, West Bengal and State Govt. of Sikkim, Damodar Valley Corporation, Durgapur Projects Ltd., National Thermal Power Corporation, National Hydroelectric Power Corpn., Powergrid Corporation Ltd., Central Electricity Authority, Eastern Regional Electricity Board, All Ministries of Govt. of India. The Prime Minister's Office, the Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for General information.

J. VASUDEVAN
Joint Secy.

